IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

बेरोजगारी के प्रति ग्रामीण शिक्षित बेरोजगारों के विचार

(जौनपुर जनपद के बक्शा विकास खण्ड पर आधारित एक समाजशास्त्रीय अध्ययन)

शोध निर्देशक
डॉ0 संजय कुमार सिंह
असिस्टेण्ट प्रोफेसर
समाजशास्त्र विभाग
सहकारी पी0जी0 कालेज
मिहरावां, जौनपुर

शोधार्थी
सुनील कुमार यादव
समाजशास्त्र विभाग
सहकारी पी0जी0 कालेज
मिहरावां, जौनपुर

शोध साहित्य सर्वेक्षण

प्रस्तावनाः–

आज बेरोजगारी की समस्या एक विश्वव्यापी समस्या बन गयी है, लेकिन इसकी विकरालता विशेष रूप से विकासशील देशों में देखने को मिलती है। बेरोजगारी किसी एक देश की समस्या न होकर विश्व की समस्या है। भारत में बेरोजगारी की समस्या देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में बहुत बड़ी बाधा है। हमारे देश की जनसंख्या का बहुत बड़ा वर्ग बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा है। इस समस्या के कारण देश का भविष्य मानी जाने वाली युवा पीढ़ी कुण्ठा, निराशा, विषाद, असुरक्षा और आक्रोश की भावना का शिकार होती जा रही है। जिस कारण अर्थोपार्जन के नकारात्मक तरीकों को युवा पीढ़ी करने में नहीं हिचकिचा रही है। वर्तमान में चोरी, हत्या, लूट, डकैती, बम विस्फोट आदि की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यदि इन घटनाओं की गहराई में जाने की कोशिश करें तो दो तत्व स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आते हैं, बेराजगारी और गरीबी।

व्यक्ति को अपने जीवन में कई भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं, जिनमें से उसकी अधिकतम निर्णायक भूमिका काम करने वाले सदस्य की है यह निर्णायक इसलिए है कि व्यक्ति की भूमिका को निभाने में जीवन का एक तिहाई भाग लगा देता है। अपितु इसलिए कि यह उसकी आजीविका एवं

प्रस्थिति का निर्धारण करती है तथा उसको अपने परिवार की सहायता और अपने समाज के दायित्वों को पूरा करने के योग बनाती है। यह उसे शक्तिशाली भी बनाती है। बेरोजगारी को समाज की सबसे महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय समस्या कहा गया है। रोजगार के अवसर होने चाहिए।

रोजगार के समान अवसर ही अर्जित प्रस्थिति को समान रूप से प्राप्त करने के लिए पूर्वपेक्षा है। प्रथम रोजगार की प्रस्थिति का उपशमन करना और दूसरा बेरोजगार को ही खत्म करना। चूँकि स्थानीय समुदाय इस समस्या को सुधारने में असमर्थ रहे हैं। अतः केन्द्र व राज्य सरकार दोनो ने मिलकर इस समस्या को अपने हाथों में लिया। फिर भी वे इसे सुलझाने में प्रभावशाली नहीं रहें और उन व्यक्तियों को जो आत्म निर्भर नहीं हैं, उन्हें सहायता प्रदान नहीं कर पायी।

भारत एक ऐसा देश है जहाँ शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। जहाँ तक शिक्षित बेरोजगारों की संख्या का प्रश्न है इसमें दिन प्रतिदिन इजाफा हो रहा है। भारत जैसे विकासशील देश में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण जनसंख्या का तीव्र गति से बढ़ना है जनसंख्या के तीव्र गति से बढ़ने के कारण श्रम–शक्ति में तेजी से वृद्धि हो रही है।

बेरोजगारी व्यक्ति के जीवन को छिन्न–भिन्न कर देती है और उसके पारिवारिक जीवन पर कुप्रभाव डालती है। बेरोजगारी व्यक्ति में निराशा और हीनता की भावना पैदा करती है। अपराध एवं पारिवारिक विघटन को जन्म देती है। व्यक्ति समाज और राष्ट्र के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से यह आवश्यक है कि बेरोजगारी की समस्या को युद्ध स्तर पर हल किया जाय। रोजगार की सुविधायें उपलब्ध करायी जाय। भारत में शिक्षा और जीविका के साधनों में न तो कोई सामंजस्य है और न कोई संतुलन तकनीकी स्नातक से लेकर, विज्ञान, कला और वाणिज्य के परास्नातक लाखों की संख्या में आज बेरोजगार हैं।

उन देशों में बेकारी की समस्या भयानक और गम्भीर बनती जा रही है जिनकी जनसंख्या अत्यधिक है, जैसे भारत। इस दृष्टि से भारत में बेकारी की समस्या एक भयानक आर्थिक सामाजिक समस्या का रूप धारण करती जा रही है। आज तीसरी दुनिया की चर्चा विश्व के कोने–कोने में हो रही है। ये मूलतः वे देश हैं जहाँ यूरोप के देशों ने शासन किया है। इन देशों ने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका का मनचाहे रूप में शोषण किया है। इन्हें हम आज अर्ध विकसित देशों की संज्ञा देते हैं।

भारत शताब्दियों तक साम्राज्यवाद और पूँजीपतियों के अधीन रहा है इसलिए बेरोजगारी की जड़े भी उतनी गहरी है। चन्द्रगुप्त मौर्य से लेकर अंग्रेजी शासन काल तक भारत में बेरोजगारी रही है बल्कि समय के साथ इसमें निरन्तर वृद्धि हुई है। आज इसने भयानक रूप धारण कर लिया है। आज यह न केवल भारत बल्कि विश्व की आर्थिक समस्या के रूप में, संकट सूचक है।

आंकड़ो के मुताबिक देश में बेरोजगारी की संख्या 10 करोड़ से अधिक है। सबसे खराब स्थिति पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, झारखण्ड, बिहार, ओड़िशा और असम की है।

वहीं सबसे अच्छे राज्यों में गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु है।

यद्यपि बार–बार कहा जाता है कि स्वतंत्रता के पश्चात हमारे देश में बेरोजगारी की चौंकाने वाली वृद्धि हुई है परन्तु बेरोजगार व्यक्तियों की सही संख्या अभी तक मालूम नहीं क्योंकि योजना आयोग या राष्ट्रीय प्रतिदर्श संगठन (National Sample Survey Organization on NSSO) ने इसका सर्वेक्षण नहीं किया है। इसलिए जो आंकड़े उपलब्ध हैं, वे अनुमानित ही हैं। ये अनुमान केवल रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत व्यक्तियों की ही संख्या को ध्यान में रखकर बनाएं जाते हैं और ये रोजगार कार्यालय विशेषतया शहरी क्षेत्रों का ही विवरण देते हैं। फिर भी सामाजिक वैज्ञानिकों में से अधिकांश इस मत के हैं कि कार्यरत जनसंख्या (Working Population) का एक बड़ा हिस्सा अपने देश में नियमित रूप से सेवायुक्त नही है और यह कि इन बेरोजगारों और सेवायुक्त व्यक्तियों और उनके परिवारों को अपनी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के लिए भी अपने परिवार के सदस्यों या रिश्तेदारों पर निर्भर रहना पड़ता है।

- एक बेरोजगार व्यक्ति वह है जिसमें कमाने की अन्तर्निहित क्षमता और इच्छा दोनो है फिर भी उसे वैतनिक काम नहीं मिल पाता।
- समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से बेरोजगारी की परिभाषा इस प्रकार की गई है कि 'यह सामान्य कार्यरत बल (Working force) के एक सदस्य (यानी 37–59 आयु वर्ग का) को सामान्य कार्य बल (Working time) में सामान्य वेतन पर और उसकी इच्छा के विरूद्ध वैतनिक कार्य से अलग रखना है।'
- डी0 मैलो ने परिभाषा देते हुए कहा है कि 'यह वह परिस्थिति है जिसमें एक व्यक्ति इच्छा के बावजूद वैतनिक व्यवसाय की स्थिति में नहीं है।'
- नाबा गोपालदास ने बेरोजगारी को 'अनैच्छिक निष्क्रियता की स्थिति बतलाया है। भारत के योजना आयोग ने उस व्यक्ति को बेरोजगार कहा है जो एक सप्ताह में एक दिन बगैर

काम के रहता है। इसके विपरीत अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने उस व्यक्ति को कार्यरत माना है जिसके पास एक सप्ताह में 15 घंटे काम होता है।

बेरोजगारी के तीन तत्व होते हैं:–

(i) व्यक्ति में काम करने की क्षमता होनी चाहिए।

(ii) व्यक्ति में काम करने की इच्छा होनी चाहिए।

(iii) व्यक्ति को काम ढुढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए।

पूर्ण रोजगारी वाले समाज की चार विशेषताएं होती है।

(1) व्यक्ति को अपनी क्षमताओं और योग्यताओं के अनुरूप वैतनिक कार्य ढूँढने में बहुत कम समय लगता है।

(2) उसको वैतनिक काम मिलने का पक्का विश्वास होता है।

(3) समाज में काम के खाली स्थानों की संख्या काम ढूढ़ने वालों की संख्या से अधिक होती है।

(4) काम पर्याप्त वेतन पर उपलब्ध होता है।

यद्यपि यह बार–बार कहा जाता है कि स्वतंत्रता के पश्चात् हमारे देश में बेरोजगारी की चौकौने वाली वृद्धि हुई है परन्तु बेरोजगार व्यक्तियों की सही संख्या अभी तक मालूम नही है क्योंकि योजना आयोग (नीति आयोग) या राष्ट्रीय प्रतिदर्श संगठन (National Sample Survey Organization-NSSO) ने इसका सर्वेक्षण नही किया है। इसलिए जो आंकड़े हैं, वे अनुमानित ही है। ये अनुमान केवल रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या को ध्यान में रखकर बनाये जाते हैं और ये रोजगार कार्यालय विशेषतया शहरी क्षेत्रों का ही विवरण देते हैं। रोजगार कार्यालयों में क्योंकि पंजीकरण स्वैच्छिक होता है, इसलिए सभी बेरोजगार इन कार्यालयों में अपना नाम पंजीकृत नहीं करवाते हैं।

देश में जबकि 1952 में लगभग 850 रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेकार व्यक्तियों की संख्या 4. 37 लाख थी, 1967 में यह बढ़कर 27.40 लाख, 1971 में 50.99 लाख, 1976 में 93.26 लाख (सूर्या, जनवरी, 1979: 50–51), 1981 में 178.3 लाख, 1983 में 219.5 लाख, 1985 में 262.7 लाख,

1987 में 302.4 लाख, 199 में 346.3 लाख और 1991 में 363.0 लाख हो गई (इन्डिया, 1992–296)।

भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गयी नवीनतम सूचना के अनुसार रोजगार चाहने वाले ऐसे शिक्षितों एवं अशिक्षितों, जो ग्रामीण तथा शहरी दोनो ही क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं तथा जिनका पंजीकरण रोजगार कार्यालयों में 31 दिसम्बर, 2009 तक दिया जा चुका था, की कुल संख्या 381.52 लाख है।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (NSSO) के निष्कर्षों, जो इस श्रृंखला में नवीनतम है, के अनुसार भारत में बेरोजगारी की दर में जुलाई 2011 से जून 2012 के मध्य वृद्धि हुई है।

ग्रामीण क्षेत्रों में यह वृद्धि दर 2 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 3 प्रतिशत रही है। प्रत्येक 1000 की जनसंख्या की जनसंख्या पर बेरोजगारी का आंकड़ा 27 का है। जबकि दो वर्षों पूर्व यह संख्या 25 पर थी। 1 जनवरी 2010 तक के कुल बेरोजगार लोगों की संख्या 98 लाख थी। 1 जनवरी 2012 तक यह बढ़कर 1.08 करोड़ हो चुकी थी।

ग्रामीण क्षेत्रों में पुरूषों तथा महिलाओं दोनों के ही लिए बेरोजगारी की दर लगभग समान स्तर अर्थात् 2 प्रतिशत पर है किन्तु शहरी क्षेत्रों में पुरूषों की अपेक्षा महिलाएं अधिक बेरोजगार हैं। महिलाओं के लिए यह दर 5 प्रतिशत है तथा पुरूषों के लिए 2 प्रतिशत (Times of India, 23 JUNE, 2013)।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

आहूजा राम– सामाजिक समस्यायें, रावत प्रकाशन।

टाइम्स आफ इण्डिया–23 जून 2013.

नगरीय समाजशास्त्र, वीएन सिंह